खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गोगोई) : (क) जुलाई, 1991 की नई औद्योगिक नीति के अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र सहित उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी पूंजी निवेश की अनुमति दी गयी है। विदेशी/अनिवासी भारतीय पूंजी-निवेश वाली खाद्य प्रसंस्करण कम्पनियों को अपने उत्पाद के विपणन क लिए विद्यमान और भावी घरेलू उद्योगों से प्रतिस्पर्द्धा करनी होती है। मंत्रालय को इस आशय की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है कि इसके कारण भारतीय कम्पनियों को वित्तीय नुकसान हो रहा है :

(ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में हैं अतः सभी खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की संख्या और इनमें कार्यरत लोगों की सख्या के बारे में सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती।

(ग) रोजगार पैदा करने, मूल्य वर्धन और निर्यात की संभावना को समझते हुए सरकार ने खाद्य प्रसस्करण उद्योगों के विकास को उच्च प्राथमिकता दी है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के समग्र विकास के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने अनेक विकासात्मक योजना स्कीमें भी तैयार की हैं और उन्हें लागू किया जा रहा है।

Expert Committee on Food Processing Sector

1083. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA : Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state :

(a) whether Government had set up an Expert Committee in the food processing sector to help the Government in formulating its policy ;

(b) if so, whether the expert committee had submitted reports to Government; and

(c) if so, the details of changes now Government propose to make in its food processing policy ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI TARUN GOGOI) :

(a) to (c) An Expert Committee has been set up to study the existing status of Food Processing Industries in the North-Eastern States and to suggest long-term and short-term action plans for development of food Processing Industries there. The Committe is expected to submit its Repor shortly

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के के लिए प्राप्त हुए ज्ञापन

1084. **डा० जितेन्द्र कुमार जैन :**
श्री राम जेठमलानी :

(क) क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जुलाई, 1991 से मार्च, 1993 तक की अवधि के दौरान देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की इकाईयों को स्थापित करने के लिए 2042 औद्योगिक उद्यम संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो कितनी इकाईयों को स्वीकृति प्रदान की गई है;

(ग) क्या शेष इकाईयों के संबध में कोई निर्णय ले लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो कितने प्रस्तावों को रद्द किया गया है तथा कितने प्रस्ताव विचाराधीन हैं;

(ङ) प्रस्तावों को रद्द किए जाने के क्या कारण हैं;

(च) क्या यह सच है कि देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना के लिए कच्चे माल के प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने की सभावना है; और

(छ) यदि हां, तो ऐसी औद्योगिक इकाईयों की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान करने क लिए निर्णय लेने में विलंब के क्या कारण हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गोगोई) : (क) से (छ) उपलब्ध सूचना के अनुसार जुलाई, 1991 से मार्च 1993 की अवधि में 2015 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन प्रस्तुत किये गए थे। इन मामलों में अलग से किसी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती अत: इन्हें अस्वीकृत करने का प्रश्न नहीं उठता। रोजगार पैदा करने, मूल्यवर्धन और निर्यात की संभावना को समझते हुए सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास को उच्च प्राथमिकता दी है। कुछ खाद्य उद्योगों के लिए कच्चा माल देश में उपलब्ध है किंतु अच्छी श्रेणी के उत्पाद तैयार करने के लिये कुछ किस्मों का विकस करना भी आवश्यक है

Setting up of Small Agro based food processing Industries in Rural areas

1085. SHRI S.K.T. RAMACHANDRAN : Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state :

(a) whether it is a fact that setting up of series of agro based food processing industries with available agricultural produce as raw materials can alone ease the stress of labour on farm lands and reduce the tendency of migration from rural to urban areas and improve the lots of the agriculturists and landless labourers in the rural areas; and

(b) if so, what steps are being taken by Government to set up such series of small agro based food processing industrial units in the rural areas suiting to the respective conditions of the local area concerned ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI TARUN GOGOI) :

(a) and (b) Considering the potential for employment generation, value addition and export, Government have accorded high priority for development of agro food processing industries. While the Ministry of Food Processing Industries does not set up food processing industries directly in any State, it has formulated several developmental. Plan Schemes for the development of food processing industries, for implementation during the Eight Plan. Under these Schemes, financial assisstance is provided to State Government Organisations, Joint Sector Companies, Cooperatives Societies, Voluntry Agencies etc. for setting up/upgrading food processing industries. One of our Plan Schemes envisages setting up of food Processing Training Centres in rural areas, which will provide a 'Hands-on' experience in operating and managing a small unit.

मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की संभावनाएं

1086. **श्री राधाकिशन मालवीय : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मध्य प्रदेश में फलों और सब्जियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है;

(ख) क्या सरकार ने इस राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के क्षेत्र में निवेश करने के संबंध में कोई आकलन किया है अथवा कराने का विचार रखती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस उद्योग के कौन-कौन से क्षेत्रों के लिए प्रोत्साहन दिए जाने का विचार है तथा यह प्रोत्साहन किस सीमा तक दिये जाने का विचार है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गोगोई) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास को उच्च प्राथमिकता दी है। उदारीकरण के बाद अगस्त, 1991 से जनवरी, 1994 तक मध्य प्रदेश के मामले में 210 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन प्रस्तुत किये गए हैं जिनमें करीब 18.68 करोड़ रु० का पूंजी-निवेश